जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 172 प्रभात चूरू, शुक्रवार 18 अक्टूबर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

लंदन में मुख्यमंत्री का पर्यटन, हीरा निर्माण, ऑटोमोबाइल व संचार सैक्टर पर जोर

प्रतिनिधिमंडल के साथ भजनलाल शर्मा ने ब्रिटेन की मंत्री व भारतीय मूल के सांसदों के साथ बैठक की

लंदन, 17 अक्टूबर । यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों के साथ सफल संपर्क के बाद, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिये विशेष अभियान चला रही है। राजस्थानी समुदाय को भावात्मक रुप से जोड़ने तथा निवेश के लिये प्रेरित करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है।

ब्रिटेन सरकार की मंत्री (इंडो-पैसिफिक क्षेत्र) कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। बैठकों के दौरान, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित "राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024" में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया।

इसके बाद, मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.), हीरा निर्माण, और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की यू.के. स्थित फर्मों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन बैठकों में एलीमेंट सिक्स (डी बीयर्स ग्रुप की कंपनी जो सिंथेटिक डायमंड, प्रोसेसिंग टूल्स आदि का कारोबार करती है), स्यानकॉनोड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन सरकार की मंत्री (इण्डो पैसिफिक क्षेत्र) कैथरीन वैस्ट के साथ मुलाकात की और लंदन के पैलेस ऑफ वैस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद का दौरा किया।

कोटा में कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 17 अक्टूबर (निसं)। दादाबाड़ी थाना इलाके में एक और कोचिंग छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी था और कोटा में मेडिकल एन्ट्रैंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वह दादाबाड़ी, शास्त्री नगर स्थित एक मकान में रहता था।

जानकारी मिलने के बाद, दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर एम.बी.एस. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दादाबाड़ी थाना अधिकारी

- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी छात्र, मैडिकल एंन्ट्रैंस की तैयारी कर रहा था। उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की।

नरेश कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल छात्र की आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। आशुतोष नाम का बीस वर्षीय यह छात्र मिर्जापुर जिले के अतीकपुर निवासी भुवनेश्वर चौरसिया का पुत्र था। पुलिस ने आत्महत्या के संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि छात्र ने आत्म हत्या क्यों की। पुलिस ने कमरे को सीज़ कर दिया है।

सी.आई. नरेश कुमार मीणा का कहना है कि आशुतोष जिस मकान में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत के खिलाफ ट्रूडो के तेवर क्यों ढीले पड़े?

अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में चर्चा है कि अमेरिका के दबाव में ट्रूडो ने सुर बदले हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रुख में भारत का नाम खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़े जाने के मामले में रुख में आए परिवर्तन को लेकर इस मामले में अमेरिका के प्रभाव के बारे में कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रूडो ने माना है कि उन्होंने शुरु में जो दावे किए थे उसकी पुष्टि के लिए उनके पास पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे। अटकले हैं कि ट्रूडो पर अपने बयान से पलटने के पीछे अमेरिका का दबाव है।

शुरु में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कैनडा में निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया था। इस दावे ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा और दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। लेकिन अब पर्याप्त सबूत नहीं होने की स्वीकारोक्ति पर सभी हैरान है कि क्या इस अचानक ह्रदय परिवर्तन के पीछे बाहरी दबाव है।

विश्लेषक कहते हैं कि इसमें संभवतया अमेरिका की भूमिका है। भारत और कैनडा दोनों ही अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। इनके बीच में संतुलित व स्थायी सम्बंध अमेरिकन विदेश नीति के भी हित में है। राजनैतिक विश्लेषक हर्ष वी. पंत ने कहा कि हो

- ज्ञातव्य है कि बुधवार को ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि, उसके एक दिन पहले ही दोनों देशों का तनाव इतना बढ़ गया था कि भारत ने कैनडा के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया था और अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था।
- विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि उसके दोनों समर्थक देशों के बीच संबंध सामन्य रहें, इसीलिए उसने कैनडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर दबाव डाला है।
- पर, कैनडा में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और ट्रूडो को अपने इस बदले रुख से भारी नुकसान हो सकता है। उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता व सामर्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं।

सकता है अमेरिका ने कैनडा का अपना रुख बदलने के लिए कहा हो। ताकि इण्डो पसैफिक रेंज में स्थिरता बनी रहे।

इसके अलावा बाइडन प्रशासन भारत से अच्छे सम्बंध चाहता है खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है वॉशिंगटन ने ही ओटावा से अपना रुख नरम करने के लिए कहा हो।

ट्रूडो के बदले रुख ने उनके नेतृत्व और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का तर्क है कि उनकी सरकार के आरोप सबूतो पर आधारित होने की बजाय राजनीति से प्रेरित थे, उन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए यह बात कही थी। कैनडा के राजनैतिक विशेषज्ञ शाची कर्ल ने कहा ट्रूडो की छवि प्रभावित हो सकती है खासकर इसलिए क्योंकि वे विदेशी दबाव में काम करते दिख रहे हैं।"

ट्रूडो पर दबाव है कि वे मजबूत व स्वतंत्र नेतृत्व प्रदर्शित करे। चुनाव सन्निकट है इलिए इस मसले को चतुराई से हल करना होगा।

ट्रूडो के इस बदले रुख से भारत के पास सम्बंध सुधारने का मौका है। भारत निज्जर की हत्या में शामिल होने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र व झारखंड के चुनावों के बाद नए राज्यपाल नियुक्त करेगी भाजपा

चर्चा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कई राज्यपालों को बदल दिया जाएगा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। कई राज्यपालों के कार्यकाल के तीन से पाँच वर्ष पूरे होने के साथ ही, एन.डी.ए. सरकार ने विभिन्न राजभवनों में होने वाले खाली स्थानों को भरने के लिये उम्मीदवारों की तलाश शुरु कर दी है। आरिफ मोहम्मद खान केरल गवर्नर के रूप में अपने पाँच साल पूरे कर चुके हैं तथा सम्भवतः किसी अन्य राज्य के राज्यपाल पद के लिये प्रतीक्षाकक्ष में बैठे हैं। इस बारे में अटकलें जोरों पर हैं कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेन्द्र कुमार जोशी, जो भारतीय नौ सेना के प्रमुख रह चुके हैं, को केरल का प्रभार दिया जायेगा।

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपने पद पर चार वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा उनको लेकर ऐसी अटकलें हैं कि उनके स्थान

- सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता राम माधव को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक केन्द्रशासित प्रदेश है, इसलिए यह पद बेहद ताकतवर है।
- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, पूर्व नौ सेना प्रमुख देवेन्द्र कुमार जोशी को केरल भेजे जाने की चर्चा है।

पर भाजपा के पूर्व महासचिव राम माधव लाये जायेंगे। माधव कई साल से उपेक्षित स्थिति में है, उसी समय से, जब जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उनका नाम लेते हुये यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बिजली के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिये उन्हें (मलिक) प्रभावित करने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि पिछले वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माधव के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर चुनावों से पहले उस समय वे पुनः प्रतिष्ठित कर दिये गये थे, जब उन्हें चुनावों के लिये भाजपा का सह-प्रभारी बनाया गया था। सूत्रों ने कहा कि माधव को उनके प्रदर्शन के लिए पुरुस्कृत किया जाएगा, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस को इस क्षेत्र में केवल एक सीट तक सीमित कर दिया था।

गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल आरक्षण 60 दिन पहले ही होंगे

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर। रेलवे ने यात्री गाड़ियों के लिए आरक्षण कराने की अधिकतम सीमा 120 दिन से घटाकर फिर से 60 दिन कर दी है। रेल मंत्रालय में इस आशय का आदेश बुधवार को जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक एक नवंबर से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा

- रेलवे ने आरक्षण कराने की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी। यह निर्णय 1 नवम्बर से लागू होगा।

की तिथि को छोड़कर) कर दी जाएगी, हालाँकि 120 दिनों के 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।

दिनांक एक नवंबर से, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ए.आर.पी.) 60 दिनों (यात्रा के दिन को छोड़कर) की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। तथापि, 60 दिनों की ए.आर.पी. के बाद की गई बुकिंग को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में शराब दुखांतिकाओं पर उठा राजनैतिक तूफान

सीवान व सारण में हुए इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 40 की हालत गंभीर

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। सन् 2016 में बिहार में शराब की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद की एक बड़ी घटना में नकली शराब पीने से राज्य में हुई करीब 36 लोगों की मौत ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सीवान और सारण जिलों में हुई इन मौतों को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है।

डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आलोक राज ने आज बताया कि सिवान में 20 लोग तथा सारन में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही 12 लोगों को नकली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तथा इन लोगों पर सख्त कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इस घटना ने राज्य में राजनीतिक

- कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सभी विपक्षी दलों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है।
- नीतीश कुमार की सरकार ने वर्ष 2016 में बिहार में शराब बंदी लागू की थी, तब से लेकर अब तक शराब दुखांतिकाओं में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

तूफान खड़ा कर दिया है तथा प्रतिबंध के बावजूद शराब की उपलब्धता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारण जिले में नकली शराब के सेवन से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्तारुढ़ पार्टी राज्य में अवैध शराब की बिक्री रोकने में असफल रही है। "एक्स" पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, "बिहार के सीवान व सारण गांवों में अभी तक 36 लोग मर चुके हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसके लिए जिम्मेवार लोगों को सख्त सजा दी जाए।"

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "सरकार को अपनी मद्यनिषेध नीति पर विचार करना चाहिए, जो राज्य में नकली शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा पाई है।"

सी.पी.आई. (एम.एल.) विधायक सत्यदेव राम, जो सीवान की दारौली सीट से विधायक हैं, ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा, "प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश में लगा है। कम से कम 60 गांवों के लोगों ने शराब पी है। इतने बड़े स्तर पर यह नहीं हो पाता, यदि इसमें लिप्त लोगों को स्थानीय प्रशासन का प्रश्रय नहीं मिला होता।"

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक क्रोध भरे वक्तव्य में कहा, "नकली शराब से होने वाली मौतें बिहार में आम बात हो गई हैं, लेकिन कभी भी किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है। यदि प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब उपलब्ध है तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असफलता है, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में गृह विभाग संभाला है।"

इस बीच मुख्यमंत्री ने शराबकांड की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर स्थिति की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बी.सी.आर. व बार एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों को आरक्षण क्यों नहीं

जयपुर, 17 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर, दी बार एसोसिएशन जयपुर सहित, प्रदेश के बार एसोसिएशन चुनाव में महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर बी.सी.आर. सहित

- राजस्थान हाई कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तथा जयपुर व प्रदेश की बार एसोसिएशनों से जवाब तलब किया।

संबंधित बार एसोसिएशनों से जवाब तलब किया है। अदालत ने इनके पदाधिकारियों से पूछा है कि बार एसोएिशनों में महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने व 33 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल का दावा, कुख्यात हमास आतंकी याहया सिनवार मारा गया

अगर इज़रायल का दावा सत्य है तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा इज़रायल-हमास युद्ध

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। गाज़ा में एक साल से चल रहा इज़रायल-हमास युद्ध समाप्त हो सकता है, यदि इज़रायल का यह दावा सत्य है कि हमास का चीफ, खतरनाक आतंकवादी, याहया सिनवार मारा जा चुका है।

इज़रायल की मिलिटरी ने दावा किया कि आतंकवादियों के साथ एक एन्काउन्टर में हमास के कई सदस्य मारे गए। इनमें से एक की शक्ल याहया सिनवार से मिलती है। मिलिटरी का कहना है कि अभी वो इस बात की पुष्टि कर रही है।

यदि यह सत्य है, तो एक वर्ष से चले आ रहे युद्ध का यह "टर्निंग पॉइंट" हो सकता है, क्योंकि सिनवार ही वो व्यक्ति था, जिसने 7 अक्टूबर के हमास हमले की योजना बनाई थी, जिसमें इज़रायल के आबादी क्षेत्र पर किए गए हमलों में ग्यारह सौ इज़रायली नागरिक मारे गए थे तथा जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान युद्ध शुरू हुआ।

सिनवार, हमास संगठन का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी नेता था तथा उसने इज़रायल के प्रति नरम रूख या किसी भी तरह की रियायत का विरोध किया था। इज़रायल द्वारा हमास के पूर्व चीफ की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या के बाद सिनवार ने हमास के शीर्ष पद पर कब्जा कर लिया था।

अमेरिका का प्रशासन सिनवार के मारे जाने की खबर से प्रफुल्लित नज़र आ रहा है। इन्टरनैशनल न्यूज़ एजेन्सियों ने यू.एस. सूत्रों को उद्धृत करते हुए

- बताया जाता है कि सिनवार ने ही गत वर्ष 7 अक्टूबर को इज़रायली बस्तियों पर हमले की साजिश को अंजाम दिया था जिसमें इज़रायल के 1100 नागरिक मारे गए थे और उसके बाद से ही यह युद्ध शुरु हुआ था जिसमें अनेक निर्दोषों की जानें गईं हैं।
- सिनवार की मौत पर अमेरिकी प्रशासन ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि अब हमास के साथ वार्ता की और हमास की कैद से इज़रायल के बंदियों को रिहा करवाने की संभावना बढ़ गई है।
- इज़रायली सीक्रेट सर्विस लगातार सिनवार को ट्रैक कर रही थी। सिनवार लम्बे समय से अण्डरग्राउण्ड था, सितंबर में ही वह दिखा था।

कहा है कि सिनवार की उपस्थिति के बिना, युद्धबंदी समझौते पर वार्ता करना आसान होगा। इज़रायल की गुप्तचर एजेन्सी मोसाद के लिए यह एक और उपलब्धि होगी, जिसने सिनवार की गतिविधि के बारे में इज़रायली मिलिटरी को सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। सिनवार की मौत के बाद अब हमास के शीर्ष नेतृत्व के पास वो अनुभव नहीं होगा, जो सिनवार के पास था।

हमास द्वारा इज़रायल पर हमले के बाद लंबे समय से याहया सिनवार नज़र नहीं आया है। अपनी गतिविधियाँ और ठौर-ठिकाना पूरी तरह गुप्त रखने के लिए सिनवार ने कभी सक्रिय भागीदारी नहीं दर्शाई। लेकिन फिर भी इज़रायल सीक्रेट सर्विस याहया सिनवार को ढूंढ रही थी। सिनवार एकाएक सितम्बर में ही खुले में आया था। उसके तुरन्त बाद ही सिनवार ने मुस्लिम-जगत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत की थी। तथापि, इसके तुरन्त बाद ही, इन लोगों ने गुप्त रूप से मिलना शुरू कर दिया।

दूसरी तरफ, इज़रायल सिनवार की तलाश में था, तथा वह इज़रायल का प्राथमिक निशाना था। लेकिन, उसने स्वयं को इतने लम्बे समय तक छुपाये रखा, यह इस बात को दर्शाता है कि गाज़ा में हमास का नैटवर्क कितनी सफलता से इज़रायली इन्टैलिजैंस के प्रमुख टारगैट को छुपाए रख सकता है।

आशा की जा रही है कि अब हमास के उदारवादी नेता बंधकों की रिहाई की सौदेबाजी के लिये अधिक दबाव बनाएंगे। हमास के पास अब भी फिरौती के लिये बहुत सारे इज़रायली बन्दी हैं। इन बन्दियों को वापस सौंपने के मामले में हमास का इन्कार एक साल से चल रहे इस टकराव के समाधान के रास्ते में बाधा बना हुआ है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शीर्ष अदालत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को

- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश की है। वे 10 नवम्बर को कार्यभार संभालेंगे।

सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके बाद शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना हैं, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी 2019 को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत किया गया था, तब वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें 2005

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)